राष्ट्रीय संस्करण

CopyRight - Jagran.com

ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने किया ट्वीट, 'कितना अच्छा है मोदी'

>>11

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 20

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, रविवार, 30 जून 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 14

आर्थिक भगोड़ों के लिए बंद होंगे दुनिया के रास्ते

जी-20 घोषणा पत्र ▸ भारत की मांग को मिली तरजीह, आर्थिक अपराधियों के खिलाफ मोदी की मुहिम को दुनिया ने गंभीरता से लिया

अपराधियों की संपत्तियां जब्त करने को जल्द तैयार होगा अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्रपत्र

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

एक देश में आर्थिक अपराध करके दूसरे देश में पनाह लेने वाले अपराधियों के खिलाफ भारत की मुहिम को दुनिया के दिग्गज 20 देशों के समूह ने बेहद गंभीरता से लिया है। जापान के शहर ओसाका में दो दिनों की जी-20 देशों के शीर्ष नेताओं की बैठक के बाद जारी घोषणा पत्र में कहा गया है कि गंभीर आर्थिक अपराध से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर जल्द ही प्रपत्र तैयार किया जाएगा जो इन अपराधियों की संपत्तियां जब्त करने की राह खोलेगा। यही नहीं, जी-20 देशों ने भ्रष्टाचार करने वालों को किसी भी दूसरे देश में पनाह नहीं देने और उनके चोरी के धन को जब्त करने की रजामंदी दिखाई है। इसे भारत के रुख का बड़ा समर्थन माना जा रहा है क्योंकि शीर्ष बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने आर्थिक भगोड़ों के खिलाफ त्वरित और ठोस कार्रवाई की मांग की थी। शनिवार शाम मोदी सम्मेलन में हिस्सा लेकर स्वदेश लौट आए।

प्रधानमंत्री मोदी के अलावा भारत के दूसरे प्रतिनिधि भी हाल के महीनों में आर्थिक अपराध कर दूसरे देशों में छिपने वाले अपराधियों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सहयोग की अपील कर रहे हैं। भारत का यह रुख हाल के वर्षों में विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे अपराधियों की वजह से बना है। इन तीनों ने संयुक्त तौर पर भारतीय बैंकों को संयुक्त तौर पर तकरीबन 20 हजार करोड़ रुपये का चूना लगाया है। माल्या और मोदी लंदन में और चोकसी एंटीगुआ में शरण लिए हुए है जिन्हें लाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। आर्थिक भगोड़ों के मुद्दे को भारत की तरफ से दी जा रही प्राथमिकता के बारे में जी-20 देशों के लिए सरकार के विशेष प्रतिनिधि सुरेश प्रभु ने बताया, 'हम बहुत मजबूती से आर्थिक अपराधियों से निपटने के एजेंडे का प्रस्ताव कर रहे थे। हमारा मानना है कि एक देश में भारी गबन करके दूसरे देश में पैसा छिपाने वाले या शरण लेने वाले लोगों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होना पड़ेगा।' माना जा रहा है कि जी-20 में इस तरह की सहमति बनने के बाद भारत के लिए माल्या या नीरव मोदी को स्वदेश लाना आसान हो जाएगा।

एफएटीएफ को लेकर सख्ती, बढ़ेगी पाक की मुश्किलें : भारत के लिए यह भी एक तरह से कूटनीतिक उपलब्धि है कि जी-20 के घोषणा पत्र में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को और मजबूत बनाने का जबरदस्त समर्थन किया गया है। इसमें कहा गया है कि एफएटीएफ के तहत आतंकी फंडिंग या मनी लांड्रिंग या गलत तरीके जमा राशि की रोकथाम में लगी एजेंसियों के बीच ग्लोबल नेटवर्क बनाया जाना चाहिए। एफएटीएफ के तहत तय मानकों को तेजी से लागू करने की बात भी कही गई है। सनद रहे कि एफएटीएफ की हाल की बैठक में पाकिस्तान को चेतावनी दी गई है कि वह आतंकी फंडिंग रोकने के अपने अंतरराष्ट्रीय वादे से मुकर रहा है। पाकिस्तान पर इसके तहत प्रतिबंध लगाने की भी आशंका जताई जा रही है।

आतंकवाद के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल रोकने का संकल्प : जी-20 देशों ने आतंकवाद और चरमपंथ को धन मुहैया करने और उन्हें प्रोत्साहन देने में इंटरनेट के इस्तेमाल पर रोक लगाने का भी संकल्प लिया। समूह देशों ने इस बात पर जोर दिया कि इंटरनेट अवश्य ही 'खुला, मुक्त और सुरक्षित' रहना चाहिए, लेकिन यह आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह नहीं होना चाहिए। जी-20 नेताओं ने एक अलग बयान में कहा, नेता के तौर पर हमारी एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह सरकार की पहली जिम्मेदारी है कि वह आतंकवाद को रोके और उसका मुकाबला करे। अपने लोगों को आतंकवादियों से बचाने और आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों में या उन्हें प्रोत्साहन देने में इंटरनेट के इस्तेमाल को रोकने के लिए हम अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। इसमें न्यूजीलैंड हमले का जिक्र करते हुए इस बात पर सहमति प्रकट की गई कि इस तरह की कोशिशों में मानवाधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सूचना तक पहुंच जैसी मूलभूत स्वतंत्रता का अवश्य सम्मान किया जाना चाहिए।

अमेरिका को छोड़ बाकी देश पेरिस समझौते के प्रति वचनबद्ध : जी-20 के 19 देशों ने पर्यावरण सुरक्षा को लेकर किए गए पेरिस समझौते के प्रति भी वचनबद्धता दिखाई है। सिर्फ अमेरिका ही इससे अलग रहा है। वैसे भारत डिजिटल इकोनॉमी पर ओसाका घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं बना है। जापान व अमेरिका की अगुआई में बनाए गए इस घोषणा पत्र का विरोध भारत समेत अन्य विकासशील देश कर रहे हैं। इन देशों का कहना है कि यह उनकी संप्रभुता व कारोबारी हितों को प्रभावित करता है।

जापान के ओसाका में शनिवार को जी-20 देशों की बैठक के अवसर पर महिला सशक्तीकरण पर विशेष सत्र के दौरान विभिन्न देशों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रेट्र

विशेष सामग्री पेज>>11

सरोकार

ग्रामीणों ने 20 दिन में बढ़ा दिया भू-जल स्तर

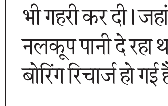

इंदौर : जिस गांव में माह भर पहले सूखे जैसे हालात थे, वहां ग्रामीणों ने पसीना बहाकर भू-जल स्तर बढ़ा दिया। लोगों ने 20 दिन में छोटा बांध बनाने के साथ ही नदी भी गहरी कर दी। जहां गांव में सिर्फ एक नलकूप पानी दे रहा था, वहां अब 150 बोरिंग रिचार्ज हो गई हैं। (पेज-13)

रविवार विशेष

खनन होगा आसान, खदानें सुरक्षित

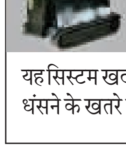

धनबाद : अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भारतीय खनि विद्यापीठ) के शोधार्थियों ने कोयला खदानों में सुरक्षा के लिए सेल्फ एडवांसिंग गोफ एज सपोर्ट सिस्टम बनाया है। यह सिस्टम खदानों को सुरक्षित कर चाल धंसने के खतरे को रोकेगा। (पेज-13)

हमारी सरकार

प्रकाश जावड़ेकर
केंद्रीय सूचना प्रसारण और वन एवं पर्यावरण मंत्री

संयम और निष्ठा की लंबी यात्रा

● पेज 6

विश्वास.News

मोबाइल पर जानलेवा जहरों के इलाज का दावा फर्जी ?

विश्वास न्यूज की पड़ताल ● पेज 5

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▸ पृष्ठ 3

राहुल पर 'अनिर्णय' में छिपा कांग्रेस का 'निर्णय'

नई दिल्ली : 'निर्णय नहीं लेना भी एक निर्णय होता है' कांग्रेस के दिग्गज नेता और दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव का यह चर्चित सूत्र वाक्य कांग्रेस के मौजूदा हालात को बिल्कुल सटीक बयान कर रहा है। राहुल गांधी के अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश के महीने भर बाद भी दोराहे पर खड़ी कांग्रेस की हालत को लेकर पार्टी कैडर की दुविधा और बेचैनी भले बढ़ रही हो, मगर अनिर्णय की यह स्थिति वास्तव में कांग्रेस की पुरानी सियासी शैली का हिस्सा रही है।

बिजनेस ▸ पृष्ठ 10

100 दिनों के एजेंडे पर रेलवे को मिली धनराशि

नई दिल्ली : चालू वित्त वर्ष के लिए पांच जुलाई को पेश होने वाले पूर्ण आम बजट में फरवरी में पेश अंतरिम बजट के अलावा नई सरकार द्वारा पेश 100 दिनों के एजेंडे की भी झलक होगी। इस वर्ष पहली फरवरी को 2019-20 के लिए पेश अंतरिम बजट में सरकार के कार्यवाहक वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे में 1.58 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत निवेश का प्रस्ताव किया था। इसमें 64,587 करोड़ रुपये की राशि बजटीय सहायता के तौर पर दी जानी थी।

क्रिकेट महाकुंभ
भारत vs इंग्लैंड
दोपहर 3:00 बजे से
स्थान : बर्मिंघम
स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

अलवर उन्मादी हिंसा में मारे गए पहलू खान को पुलिस ने बताया गो-तस्कर

▸ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट

▸ मुख्यमंत्री बोले-गड़बड़ी हुई तो फिर कराई जाएगी जांच

जागरण संवाददाता, जयपुर

अलवर में दो साल पहले उन्मादी भीड़ की हिंसा (मॉब लिंचिंग) के शिकार हुए पहलू खान (55) के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें उसे गो-तस्कर बताया गया है। उसके दो बेटों, इरशाद(25) और आरिफ (22) को भी अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस ने गायों को ले जा रहे ट्रक के मालिक को भी अभियुक्त माना है। शनिवार को पुलिस जब पूरक चार्जशीट दाखिल करने वाली थी तो यह मामला प्रकाश में आ गया। इसके बाद सांसद और एआइएमआइएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि राजस्थान में मुसलमानों को कांग्रेस का समर्थन नहीं करना चाहिए।

ज्ञात हो, हरियाणा के नूंह जिले के जयसिंहपुर गांव के पहलू की एक अप्रैल 2017 को राजस्थान के बहरोड़ में तथाकथित गोरक्षकों ने पिटाई की थी। गंभीर रूप से घायल पहलू ने चार अप्रैल को दम तोड़ दिया था। इस वाक्ये के समय राजस्थान में वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार थी। पुलिस ने इस मामले में दो एफआइआर दर्ज की थीं। एक पहलू की हत्या के मामले में नौ लोगों के खिलाफ और दूसरी बिना कलेक्टर की अनुमति के जयपुर के मेले से मवेशी ले जाने को लेकर पहलू और उसके दोनों बेटों के खिलाफ थी। प्रदेश में अशोक गहलोत के सत्ता में आने के बाद पहलू की मौत मामले में 30 दिसंबर 2018 को नौ लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई थी। ये सभी नौ आरोपित अभी जमानत पर हैं। इसके बाद 29 मई, 2019 को बहरोड़ की कोर्ट में मरणोपरांत पहलू के खिलाफ गो-तस्करी में चार्जशीट पेश की गई। इसी मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल होनी थी। इस मामले में एसपी अनिल पारिस देशमुख ने बताया कि 24 मई को कोर्ट ने राजस्थान गोवंश संरक्षण कानून-1995 के तहत तीन लोगों के खिलाफ आरोपपत्र मंजूर किया था। चूंकि पहलू की मौत हो चुकी है। इसलिए उसके खिलाफ आरोपपत्र दायर नहीं किया गया है। हालांकि, पहलू का नाम चार्जशीट की समरी में है।

वहीं, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्ञानदेव अहूजा ने कहा, पहलू और उसके बेटे आदतन अपराधी थे। वे गो-तस्करी में शामिल थे। गोरक्षकों और हिंदू परिषद पर लगाए गए आरोप गलत थे। अब जब उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है, तो कांग्रेस श्रेय ले रही है।

रिपोर्ट पर बेटे ने जताया एतराज: पहलू के बेटे इरशाद ने चार्जशीट पर एतराज जताते हुए कहा है कि गोरक्षकों के हमले में हमने पिता को खो दिया और फिर भी हमें ही गो-तस्कर बताया जा रहा है। राजस्थान की नई सरकार से हमें उम्मीद है कि वह हमारे खिलाफ दर्ज मुकदमें वापस लेगी।

गहलोत बोले- दोषियों को सजा दिलाकर रहेंगे

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पहलू खान केस की जांच पिछली भाजपा सरकार के दौरान की गई थी। इस मामले की चार्जशीट भी भाजपा सरकार के दौरान ही पेश की गई थी। अगर इस जांच में किसी भी तरह की खामी पाई जाती है तो इस मामले की जांच फिर से कराई जाएगी। हालांकि, मामला अभी कोर्ट में है, मगर हम दोषियों को सजा दिलाकर रहेंगे। कांग्रेस हमेशा से ही उन्मादी हिंसा के खिलाफ रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस का आज भी वहीं स्टैंड है कि जो पहले था।

ब्रिटेन के आकाश में पाक की करतूतों के बैनर वाला विमान

▸ क्रिकेट मैच के दौरान बलोच संगठन का जन जागरण आंदोलन

▸ मैदान के बाहर भिड़े पाकिस्तान और अफगान समर्थक

लीड्स, एएनआइ : अंतरराष्ट्रीय तौर पर पाकिस्तान की करतूतों का प्रचार जारी है। शनिवार को जस्टिस फॉर बलूचिस्तान... और अन्य नारे लिखे बैनर लगाए विमान हैडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर से गुजरा। जिस समय यह विमान ग्राउंड के ऊपर से गुजरा उस समय वहां क्रिकेट विश्व कप के अंतर्गत पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच चल रहा था। इस दौरान ग्राउंड के बाहर दोनों देशों के समर्थक आपस में भिड़ गए। मैच के बाद भी दोनों देशों के समर्थक फिर भिड़े। इस दौरान फेंकी गई बोतल से ग्राउंड में बने प्रेस बॉक्स का शीशा टूट गया।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) ने कहा है- विमान का राजनीतिक मकसद से मैदान के ऊपर आना गैरकानूनी था, लीड्स एयर ट्रैफिक मामले की जांच करेगा। आइसीसी ने समर्थकों के टकराव पर भी नाराजगी जाहिर की है। ज्ञात हो, ब्रिटेन में कई हफ्तों से पाकिस्तान के बलूचिस्तान और सिंध प्रांतों में मूलवासियों और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों पर हो रहे अत्याचारों के प्रति जन जागरण का अभियान चल रहा है। पाकिस्तान में बलोच आबादी पर हो रहे अत्याचार का मामला काफी पुराना है। पाकिस्तान के बाहर जब जहां मौका मिलता है बलोच संगठन इस उत्पीड़न के बारे में प्रचार कर मदद की गुहार लगाते हैं।

ब्रिटेन में विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट के मौके को भी बलोच संगठनों ने पाकिस्तान की असलियत बताने के लिए चुना है। शनिवार को क्रिकेट मैच के दौरान बलूचिस्तान के लिए न्याय की मांग और वहां रहने वालों की हत्या, उन्हें गैरकानूनी रूप से जेल में डालने और मानवाधिकारों के उल्लंघन के नारे लिखे बैनर लगाए विमान ग्राउंड के ऊपर से दो बार गुजरा। बैनरों पर काले और लाल रंगों में बड़े-बड़े अक्षरों से ये नारे लिखे हुए थे। इस तरह के असामान्य जन जागरण ने ग्राउंड में मौजूद लोगों का ध्यान खींचा और लोग तब तक विमान को देखते रहे, जब तक वह आकाश में ओझल नहीं हो गया। इसके कुछ देर बाद ग्राउंड के बाहर पाकिस्तान व अफगानिस्तान के समर्थक भिड़ गए। अफगानी क्रिकेट समर्थक बलोच आबादी की मांग का भी समर्थन कर रहे थे। टकराव का माहौल देखते हुए पुलिस और ग्राउंड की सुरक्षा से जुड़े लोगों ने हस्तक्षेप किया और हाथापाई कर रहे समर्थकों को मौके से हटाया। वर्ल्ड बलोच ऑर्गनाइजेशन ने ट्वीट कर अपने अभियान की ओर ध्यान देने के लिए लोगों का आभार जताया और समर्थन मांगा है। इससे पहले 23 जून को भी लॉर्ड्स में पाकिस्तानी टीम के दक्षिण अफ्रीका से मैच के दौरान स्टेडियम के बाहर बलोच संगठनों ने पाकिस्तान की बलूचिस्तान नीति को लेकर प्रदर्शन किया था।

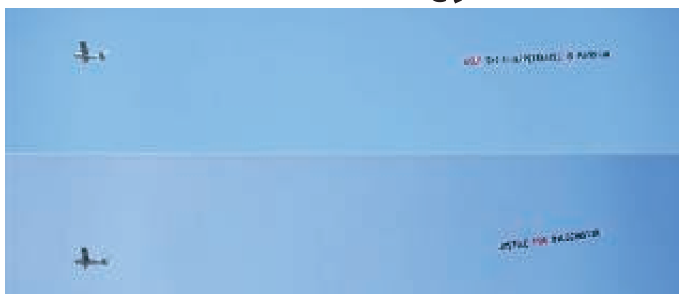

लीड्स में पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच क्रिकेट मैच के दौरान मैदान के ऊपर से गुजरे विमान से 'जस्टिस फॉर बलूचिस्तान और हेल्प इंड डिसएपियरेंसेज इन पाक' लिखे बैनर लहराए गए। ट्विटर

> हम कुछ प्रशंसकों की घटिया हरकत से वाकिफ हैं और पुलिस से संपर्क में हैं। वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस ने हमसे कहा है कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। ऐसी हरकतें जिनसे प्रशंसकों के लुत्फ में कमी आए, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। विश्व कप में ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। – आइसीसी

पुणे में बड़ा हादसा

महाराष्ट्र में पुणे जिले के कोंढवा इलाके में मूसलधार बारिश से शुक्रवार देर रात एक हाउसिंग सोसाइटी के परिसर की दीवार ढह गई, जिसके नीचे दब कर 15 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र और बिहार सरकार ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद की घोषणा की है। (खबर पेज-5 पर) प्रेट्र

चार महीने बाद आज फिर से करेंगे मोदी मन की बात

नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)

नई दिल्ली, एएनआइ : लोकसभा चुनाव की व्यस्तताओं के बीच करीब चार माह के अंतराल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को फिर से मन की बात करेंगे। यह उनके दूसरे कार्यकाल का पहला 'मन की बात' कार्यक्रम होगा। बता दें कि फरवरी 2019 में मोदी ने आखिरी मन की बात कार्यक्रम किया था। उस दौरान उन्होंने चुनावों में जीत पर भरोसा जताते हुए कहा था कि कि अगली मन की बात चुनावों के बाद करेंगे। रेडियो पर प्रसारित होने वाला यह कार्यक्रम माह के आखिरी रविवार को प्रसारित किया जाता है।

सरकार की योजना

मोदी सरकार के पास विचाराधीन है इस बारे में एक योजना, इस पर अमल हुआ तो आतंकी के जनाजे के बाद जेहादी भाषण नहीं होंगे, न ही सोशल मीडिया पर वायरल होंगी तस्वीरें और वीडियो

आतंकियों के जनाजे में नहीं जुटेगी भीड़

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के जनाजे में अब भीड़ जमा नहीं होगी। न जेहादियों के भाषण होंगे, न जनाजे की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने दिए जाएंगे। इसके लिए एक योजना केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है, जिसका मकसद आतंकियों के जनाजे को नए जेहादियों की भर्ती का जरिया बनने से रोकना है।

2015 में ऊधमपुर हमले के मास्टरमाइंड अबु कासिम के जनाजे में हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। इसके बाद घाटी में यह सिलसिला चल निकला और आतंकियों का जनाजा नए आतंकियों की भर्ती का जरिया बन गया। प्रशासन ने इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए विदेशी आतंकियों के शव स्थानीय लोगों को सौंपने के बजाय खुद ही गुमनाम जगह पर दफनाना शुरू कर दिया। स्थानीय आतंकियों के शव उनके परिजनों के हवाले किए जाते हैं, जिनमें खूब भीड़ उमड़ती है। आतंकी कब्रिस्तानों में पहुंच कर हवा में गोलियां दाग कर अपने साथियों को सलामी देते हैं। कई उलेमा और आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्कर जेहादी भाषण देते हैं। ये लोग जनाजे में आई भीड़ को कश्मीर में भारत के खिलाफ रेफरेंडम के तौर पर दिखाने की कोशिश भी करते हैं।

क्या है जनाजे को जुलूस में बदलने से रोकने की तैयारी : आतंकरोधी अभियान से जुड़े एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रस्तावित योजना के मुताबिक, किसी भी मुठभेड़ में स्थानीय आतंकी की मौत होने पर उसकी पहचान को तब तक गुप्त रखा जाएगा, जब तक उसके पैतृक इलाके में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षाबल तैनात नहीं कर दिए जाते। इसके बाद ही उसके परिजनों को शव सौंपा जाएगा। इसके बाद भी जनाजे को जुलूस में बदलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आतंकी को जिस कब्रिस्तान में दफनाया जाना होगा, वहां अन्य लोगों की आवाजाही रोक दी जाएगी और सिर्फ मारे गए आतंकी के परिजन और चंद रिश्तेदार ही जनाजा लेकर आएंगे। मौके पर एक मजिस्ट्रेट, मजहबी नेता और ओकॉफ कमेटी के सदस्य रहेंगे। मजहबी रस्मों के साथ आतंकी को दफनाया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी।

गृहमंत्री के साथ हुई बैठक में उठा मुद्दा : एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में भी यह मुद्दा उठा था। इस सिलसिले में एक प्रस्ताव भी केंद्रीय गृहमंत्री को सौंपा गया है। उस पर अभी गृहमंत्रालय अपने स्तर पर चर्चा करेगा और उसके बाद ही इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

आतंकी के महिमामंडन से बनते हैं नए आतंकी

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि दक्षिण कश्मीर में कराए गए सर्वे से पता चला है कि आतंकियों के जनाजे और उनका महिमामंडन, नए जेहादियों की पौध के लिए खाद का काम करता है। इसलिए आतंकियों के जनाजे में भीड़ रोकने का प्रस्ताव तैयार किया गया। उनके मुताबिक, मुठभेड़ में मारे गए आतंकी का शव उसके परिजनों को सौंपने के बजाय सुरक्षाबल ही उसे स्थानीय ओकॉफ कमेटी की मदद से दफन करें, लेकिन इसमें कई तरह की मुश्किलें थीं, इसलिए यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ा था।

नीरव मोदी से भी बड़ा है संदेसरा बंधुओं का घोटाला

▸ प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक, 14,500 करोड़ रुपये तक पहुंचा घोटाला

▸ नीरव मोदी ने पीएनबी के साथ किया था 11,400 करोड़ का घपला

▸ संदेसरा समूह को प्रमुख बैंकों के कंसोर्टियम ने पास किया था ऋण

नितिन और चेतन संदेसरा (फाइल फोटो)

नई दिल्ली, एएनआइ : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का दावा है कि संदेसरा बंधुओं ने नीरव मोदी से बड़ा बैंक घोटाला किया है। ईडी ने कहा कि जांच में स्टर्लिंग बॉयोटेक लि. (एसबीएल)- संदेसरा समूह और इसके प्रमोटरों, नितिन संदेसरा, चेतन संदेसरा और दीप्ति संदेसरा ने भारतीय बैंकों के साथ लगभग 14,500 करोड़ रुपये का घोटाला किया जबकि नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक के 11,400 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप है।

पहले सीबीआइ फिर ईडी ने दर्ज की एफआइआर : सीबीआइ ने 5,383 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले के आरोप में संदेसरा समूह की कंपनियों और उसके प्रमोटरों के खिलाफ अक्टूबर 2017 में एफआइआर दर्ज की थी। उसके बाद ईडी ने भी एफआइआर दर्ज की। ईडी को जांच में पता चला कि संदेसरा समूह की विदेशों में स्थित कंपनियों ने भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं से 9 हजार करोड़ रुपये का ऋण लिया था।

विदेशी मुद्रा में भी लिया ऋण : संदेसरा समूह ने बैंकों से भारतीय रुपये के साथ-साथ विदेशी मुद्रा में भी ऋण लिया। समूह की कंपनियों को आंध्रा बैंक, यूको बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआइ), इलाहाबाद बैंक और बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई वाले बैंकों के कंसोर्टियम ने ऋण पास किया।

बैंक से मिले ऋण को किया निजी हितों में इस्तेमाल : ईडी के मुताबिक ऋण से मिली रकम का अनुमति से इतर इस्तेमाल किया गया और कुछ रकम को फर्जी देसी-विदेशी संस्थानों के जरिए इधर से उधर ट्रांसफर किया गया। मुख्य प्रमोटरों ने कर्ज की रकम न केवल नाइजीरिया में अपने तेल के कारोबार में निवेश किया, बल्कि इसका निजी उद्देश्य में भी इस्तेमाल किया।

संदेसरा समूह की ये संपत्तियां हुईं जब्त : ईडी ने 27 जून को एसबीएल-संदेसरा समूह की करीब 9,778 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की। संदेसरा की विदेश स्थित जब्त संपत्तियों में एक निजी विमान, चार जहाज, कच्चा तेल निकालने के चार प्लेटफार्म (रिग्स), एक ऑयल फील्ड और लंदन स्थित एक फ्लैट शामिल है। 200 गल्फस्ट्रीम विमान अमेरिका में पंजीकृत है। तुल्जा भवानी, वृंदा, भाव्या और ब्राह्मणी नाम के चार जहाज पनामा में पंजीकृत हैं। चार ऑयल रिग्स और ऑयल फिल्ड नाइजीरिया में हैं।

ये हैं संदेसरा समूह के प्रमोटर : नितिन संदेसरा, चेतन संदेसरा और दीप्ति संदेसरा स्टर्लिंग बायोटेक लि -संदेसरा समूह के मुख्य प्रमोटर हैं। नितिन विदेश में कारोबार संभालता है जबकि चेतन वडोदरा, मुंबई, दिल्ली व मसूरी के ऑफिस का कामकाज देखता है।